विकल्पहीनता का संकट

विशेष प्रतिनिधि

मोदी सरकार के हर मोर्चे पर फेल हो जाने के बाद यह तय हो चुका है कि अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर जीत हासिल नहीं हो सकती। अलग.अलग राज्यों में निकायों के जो चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है।

मोदी की लोकप्रियता अब अतीत की बात हो गई है। अगर आज आम चुनाव होते हैं, तो यह सरकार चारों खाने चित हो जाएगी। इतनी जल्दी किसी सरकार से जनता का मोहभंग होना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। यह भी तय कि राज्यसभा में भाजपा को बहुमत हासिल नहीं हो सकता और मोदी सरकार को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए अध्यादेशों का ही सहारा लेना पड़ेगा। पर अध्यादेश भी कब तक, सरकार के नीति.नियंताओं को यह चिंता खाए जा रही है। आरएसएस सरकार की छवि में सुधार लाने के लिए चिंतित है और इसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। संभव है, मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल में बड़ा हेरफेर करें। पर भाजपा के पास जो लोग हैं और जिस तरह आरएसएस ने सरकार पर नियंत्रण कर रखा है, उसमें कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। बुलेट ट्रेन के लिए देश को कर्जे में डालने वाली यह सरकार एक तरफ जहां लगातार रेलभाड़े में वृद्धि करती चली जा रही है, वहीं रेलमंत्री सुरेश प्रभु जो शिवसैनिक हैं, ट्विटर के जरिए चलती ट्रेन में बच्चों के लिए डायपर और नैपकिन उपलब्ध करने जैसे हास्यास्पद तमाशे कर रहे हैं और मीडिया उनका गुणगान कर रहा है।

बहरहाल, बिहार में करारी हार के बाद अब नंबर बंगाल का है, जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने बंगाल में अपनी जहरीली राजनीति के दांव चलने शुरू किए थे। शुरू में ममता बनर्जी भी मोदी के पाले में आती नज़र आई थीं, पर अब हालात बदल गए हैं। बिहार की हार ने आरएसएस को बुरी तरह हिला कर रख दिया है। मोदी तो मोहरा हैं, जिन्हें अपने भले.बुरे के बारे में सोचना नहीं, न इतनी क्षमता है उनमें। मानसिक और बौद्धिक तौर पर परले दर्जे का कमजोर आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसके लगभग सारे सहयोगी भी औसत बुद्धि से भी कम के हैं और जिन्हें सरकार चलाने का कोई खास अनुभव नहीं रहा। मोदी और उनके सहयोगियों के हाथों में सरकार वैसे ही है, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। ये जहां तक संभव हो सकेगा, देश को बर्बाद करके रहेंगे। बस चंद पूजीपतियों को जिनमें अडानी और अंबानी प्रमुख हैं, देश के संसाधन लूटने की खुली छूट मिल गई है। अन्य पूंजीपति मोदी राज में असंतुष्ट हैं। इसकी वजह ये है कि अर्थव्यवस्था ढहती चली जा रही है। मोदी के सारे कार्यक्रम रेत के महल की तरह हैं। मेक इन इंडिया से लेकर और जितनी भी घोषणाएं मोदी ने की, वे बुरी तरह असफल हुए। विदेशी निवेशकों को इस सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनता की लूट.खसोट का अभियान तेज करती चली जा रही है।

विदेश नीति के मोर्चे पर भी सरकार बुरी तरह पिट चुकी है। चीन. नेपाल.पाकिस्तान से लेकर रूस और अमेरिका तक के साथ संबंधों में मोदी सरकार का दिवालियापन सामने आ चुका है। विदेशी नेता मोदी को एक जोकर से ज्यादा नहीं मानते हैं और इनकी मूर्खताओं से अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में, मोदी राज में देश का जितना बुरा होना है, होकर रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इस सरकार के खिलाफ कहीं कोई किसी आंदोलन की सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है या अगर तीन.साढ़े तीन साल बाद जनता इस सरकार को नकारती है तो इसकी जगह कौन लेगा। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल? वामपंथियों ने कांग्रेस के साथ आने की घोषणा कर दी है। लालू.नीतीश का गठबंधन पहले ही कांग्रेस के साथ है।

वामपंथियों ने इस साल होने वाले चुनाव में ममता के विरुद्ध कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला कर लिया है। वामपंथी इस बार किसी भी तरह बंगाल में सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। इसलिए अपने विरोधी रहे कांग्रेस से हाथ मिलाने में इन्हें परहेज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, ममता की शासन शैली वामपंथियों से जरा भी अलग नहीं रही। गुंडागर्डी में ममता दीदी वामपंथियों से बीस ही पड़ीं। वहां भी जनता अब उनके कुशासन से त्राहिमाम कर रही है, पर करे तो क्या करे। जब वामपंथी शासन में थे तो उन्होंने कोहराम मचाया और ममता दीदी आईं तो उन्होंने भी गदर मचा दिया। अब अगर मोदी जी आ जाएं तो क्या होगा, यह सोच कर ही जनता कांप उठती है। ऐसे में, वामपंथियों और कांग्रेस के गठबंधन के लिए उम्मीद जगती है। पर ममता ने इसकी जो काट ढूंढी है, वह कितनी खतरनाक है, इसका पता मालदा की घटना से चलता है, जहां अल्पसंख्यकों ने जमकर हिंसा की और उत्पात मचाया। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब ममता ने कोलकाता में सिर्फ मुसलमानों की रैली बुलाई थी। यह एक साम्प्रदायिक कदम ही था, पर इसका कोई विरोध नहीं हुआ। इसके बाद बिहार के पूर्णिया में अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक उत्पात की घटना सामने आई। सवाल है, इन बातों से क्या संकेत मिलता है? संकेत यही मिलता है कि भले ही भाजपा जन असंतोष की वजह से पराजित हो जाए, पर वह विकल्प नहीं है, जिस पर जनता भरोसा कर सके। विकल्प है तो वही जिससे परेशान होकर और मोदी जी को झूठे वायदों पर भरोसा कर जनता ने भाजपा को विजयी बनाया था। अब अगर भाजपा मुंह की खाती है, जो तय है, तो विकल्प के रूप में कांग्रेस, वामपंथी और राजद.जदयू जैसी ही पार्टियां हैं। इनका जो इतिहास है, वह बताता है कि ये भी बड़े लुटेरों में शामिल रहे हैं। आखिर मोदी जी जैसे अंबानी.अडानी के टुकड़खोर के सत्ता में आने की ज़मीन तो इन्हीं दलों ने तैयार की। कांग्रेस के राज में जितने घोटाले हुए, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने नंदीग्राम और सिंगूर में जो जनविरोधी रवैया अपनाया, क्या उसे भुलाया जा सकता है? फ़िर मोदी का विकल्प ये भ्रष्ट दल ही हैं और जनता को यह स्वीकार करना होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि आरएसएस खतरनाक है और इसे किसी कीमत पर सत्ता से बेदखल करना चाहिए। यह सही है। पर क्या कांग्रेस और वामपंथी धर्मनिरपेक्ष हैं? यह ऐसा सवाल है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि आरएसएस एक उग्र हिन्दूवादी आतंकी संगठन है और भ्रष्टतम पूंजीपतियों का प्रतिनिधि है, उन परजीवी पूंजीपतियों का जिनके साक्षात प्रतिनिधि अंबानी हैं। पर क्या यही अंबानी नहीं कहता था कि कांग्रेस का दफ्तर उसका दूसरा घर है।

क्या कांग्रेस के राज में अंबानी.अडानी नहीं फूले-फले भूलना नहीं होगा कि उग्र हिन्दूवादी संगठन आरएसएस के सत्ता में आने के पीछे कांग्रेस.वामपंथी.समाजवादी और लालू.नीतीश जैसे राजनेता ही जिम्मेदार रहे हैं, जिनका एक ही लक्ष्य हमेशा रहा और अब भी है . येन.केन.प्रकारेण सत्ता पर काबिज होना। अगर भाजपा सत्ता से बेदखल होती है और कांग्रेस के नेतृत्व में कोई नया गठबंधन सत्ता में फ़िर से वापसी करने में सफ़ल हो जाता है, जिसकी सम्भावना सबसे ज्यादा है, तो यह विचार करना चाहिए कि इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा। क्या उसकी जीवन.स्थितियों में कोई बदलाव आएगा, यूपी में सैफई महोत्सव कर बॉलीवुडी सुन्दरियों का नाच देखने वाले नेता जनता के लिए कैसा विकल्प साबित होंगे, यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसे देखते हुए आरएसएस ने राममंदिर के निर्माण का राग फ़िर से छेड़ दिया है। राम.शिलाएं जमा की जा रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषणा कर दी है कि इस साल दिसंबर में राममंदिर का निर्माण होगा। आरएसएस साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश पर काम कर रहा है। पर इसके जवाब में कौन.सी शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। बस एक शून्य ही है।

देश में मज़दूरों.किसानों का कहीं कोई सही संगठन और आंदोलन दिखाई नहीं पड़ता। दूर.दूर तक जनविकल्प की कोई शक्ति आकार लेती दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में, जनता के लिए कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। चुनाव एक छलावे के सिवा और कुछ भी नहीं। सवाल है, जनता इस छलावे में कब तक छली जाएगी?

रखो शबरीमाला अपने पास

कई दिनों से शबरीमाला की खबर वायरल है। खूब पोस्ट भी लिखीं जा रही हैं। वैसे यह नई बात नहीं। दशकों पहले कभी जानकर क्षोभ हुआ था कि वहां दर्शनार्थी स्त्रियों की आयु का हिसाब रखा जाता है ताकि मन्दिर को अशुभ होने से बचाया जा सके। जो लोग दक्षिण के लोगों को करीब से जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि वहां लड़की के बड़े, हो जाने को एक उत्सव की तरह मनाने की प्रथा है और वहीं से शुरू होती उन खास दिनों में उसे अलग थलग रखने की कवायद। मेरी एक तमिल सहकर्मी ने बताया था, सामान्य मन्दिर प्रवेश तो छोड़िये, रजस्वला स्त्री को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति नहीं और इसमें विवाह भी शामिल है। मतलब वह ऐसी दशा में किसी के वैवाहिक आयोजन का भी हिस्सा नहीं बन सकती। बेशक़ आज चीज़ें बदल रही हैं किन्तु दक्षिण भारतीय मान्यताओं के अनुसार इन दिनों स्त्री को अलग बैठना होता था, वह किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती थी। किन्ही खास बर्तनों में उसे खाना वहीं दे दिया जाता था। खुद मेरे परिवार में मेरी ननद के यहाँ जब तक उनकी सास जीवित रहीं इसी प्रथा का पालन किया जाता रहा। मेरी सहकर्मी ने बताया था कि औरतें इस शर्मनाक निर्वासन से बचने के लिए डॉक्टरी मदद तक लेती हैं। यानी पारिवारिक आयोजन से पहले दवाइयों के सहारे उन खास तारीखों को पोस्टपोन करने की कोशिश करती हैं बाद में चाहे उन्हें इसके साइड इफेक्ट ही क्यों न झेलने पड़े। वैसे मुझे लगता है परिवारों के सिकुड़ने का प्रभाव ऐसी तमाम अजीबोगरीब प्रथाओं पर भी पड़ा है जबकि संयुक्त परिवार ऐसी तमाम प्रथाओं, कुप्रथाओं का पोषक होता है। पापड़ों पर छाया पड़े तो वे लाल पड़ जाएंगे, तुलसी मुरझा जाएगी, अचार सड़ जाएगा और भी न जाने क्या.क्या। खुद हिंदुओं में भी ऐसे में मन्दिर प्रवेश और पूजा पाठ की मनाही होती है। जिसके विरुद्ध दबी ढकी आवाज़ें हमेशा उठती रही हैं। हमारी पीढ़ी ने तमाम छूने न छूने या अलग थलग बैठने जैसी अजीबोगरीब प्रथाओं को जमकर नकारा है, रूढ़ियों को धता बताई है, पर पूजा पाठ या मन्दिर प्रवेश हमारी पीढ़ी की प्राथमिकता कभी नहीं रहा। यही कारण रहा होगा कि इसके विरुद्ध आवाज़ें हमने बुलन्द नहीं की। जरूरत ही महसूस नहीं हुई। पर शबरीमाला में सेंसर करने के लिए मशीन लगाने जैसी बात इतनी हास्यास्पद है कि उनकी सोच पर हंसी आती है। रखिये अपने पास अपना मन्दिर जो ईश्वर स्त्री को कमतर समझता है, जो ईश्वर अपने ही बनाए स्त्री पुरुष में भेद करता है, जो स्त्री की जीवनदायी शक्ति को उसकी कमजोरी या अशुद्धत्ता समझता है, जो ईश्वर एक को ब्राह्मण और दूसरे को दलित मानता है, ऐसा ईश्वर केवल आपका है हमारा नहीं। अव्वल तो हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत ही नहीं, जरूरत हुई तो हम अपना ईश्वर आप गढ़ लेंगे, हमारे टाइप का बिंदास, लोकतान्त्रिक और पूर्वग्रहों से मुक्त ईश्वर.....

. अंजू शर्मा

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 जनवरी 2016 के अंक में राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक वा साहित्यिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। प्रशासन व मीडिया द्वारा प्रदूषण के खतरे के मुद्दे को एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रदुषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय ग्रीन ट्रब्यूनल व राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित किए गए जिनके चेयरमैन व अधिकारी वे लोग नियुक्त किए जाते हैं जो सरकार के चहेते होते हैं। इन लोगों की प्रदूषण नियन्त्रण करने में कोई रूचि नहीं होती। ये सब लोग पुलिस की मिली भगत से केवल लोगों की लूटमार में लगे रहते हैं। प्रदूषण फ़ैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां धड़ल्ले से चल रही हैं।

इनका लेख भ्रष्टाचारियों! तुम्हारे लिये प्रदूषण बढना ही जरूरी-सम-विषम को बनाया तोड़: केजरी की तुगलकी होड़! में पूरा विवेचन किया गया है। प्रदूषण के नाम से अधिकारी, पुलिस, मीडिया तथा ऐयर प्योरिफ़ायर उपकरण बनाने वाली कम्पनियां कमाई करने में जुटी हुई हैं। ऐयर प्योरिफ़ायर बनाने वाली कम्पनियों की जारी सालाना रिपोर्ट में एक नामचीन कम्पनी के रिपोर्ट के अनुसार उसके द्वारा बनाए गए ऐयर प्योरिफ़ायर पहले एक वर्ष में जहां 10,000 बिकते थे अब एक माह में ही 10,000 उपकरण बिकते हैं। एक अन्य कम्पनी द्वारा निर्मित ऐयर प्योरिफ़ायर के विज्ञापन मीडिया द्वारा प्रसारित करके कमाई की जा रही है। परंतु प्रदूषण दिन प्रति दिन बढता जा रहा है। यदि सरकार प्रदूषण को नियन्त्रित करने में लेशमात्र भी गम्भीर होती तो प्रदूषण का स्तर इस खतरनाक स्थिति पर नहीं पहुंचता। प्रदूषण फ़ैलने के मूल कारण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिये दिल्ली में 15 दिन सम-विषम वाहन चलाने का प्रयोग किया है। लेकिन केजरीवाल ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू द्वारा सम-विषम से पुलिस के अच्छे दिन आने सम्बन्धित ब्यान द्वारा सम-विषम नीति पर व्यंग्य किया गया है। परंतु सम-विषम नीति के परिणामस्वरूप दिल्ली मैं ट्रैफ़िक नियंत्रित हुआ है, ट्रैफ़िक जाम की स्थिति में सुधार हुआ है तथा पेट्रौल-डीजल की खपत में भी कमी आई है जिससे प्रदूषण स्तर में भी सुधार हुआ है। इससे प्रेरित होकर यह फ़ार्मूला रोहतक में भी लागू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेलमंत्री सुरेश प्रभु की बुलेट ट्रेन चलाने तथा रेल व्यवस्था में कथित सुधारों की बहुत प्रशंसा की जाती है। परंतु रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने आम लोगों को रेल यात्रा में सुविधाएं प्रदान करने और रेलवे का पूर्ण विद्युतिकरण करने पर कोई जोर नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त दिल्ली की रिंग रेलवे लाइन को सुचारू रूप से चलाने की तरफ़ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि सरकार वास्तव में प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहती हैँ तो उसे ईमानदारी से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर रिंग रेलवे लाईन को सुव्यवस्थित करने, प्रदूषण फ़ैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्यवाही करने तथा एन सी आर के नगरों को विकसित करने के प्रयास की आवश्यकता है।

दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार तथा केन्द्र की मोदी-राजनाथ सरकार के बीच चल रही जंग में उप-राज्यपाल नजीब जंग की भूमिका की पाण्डु पुत्र अर्जुन तथा कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह के बीच युद्ध के दौरान शिखंडी की भूमिका से तुलना स्तम्भ 'खबर दार यदा-यदा हि धर्मस्य...' में की गई है। इस तुलना से एक सवाल खड़ा होता है कि महाभारत युद्ध के परिणाम की तरह क्या मोदी-राजनाथ अपने शिखंडी नजीब जंग के जरिए केजरीबाल को समाप्त करने में सफ़ल होंगे?

लेख 'चंडीगढ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह की बजाय मंगलसेन?' से स्पष्ट है कि केन्द्र व राज्य हरियाणा में भाजपा सरकार होने के बावजूद हरियाणा को कोई केन्द्रीय प्रोजेक्ट नहीं मिला है और देश भक्ति व शहीदों के बलिदान याद करने वाली सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की जगह संघ से जुड़े भाजपा नेता मंगल सेन का नाम रखने का प्रयास किया। इससे भाजपा की कथनी व करनी में अंतर स्पष्ट उज़ागर होता है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद मोदी सरकार कांग्रेस की जिन नीतियों की आलोचना करती थी उन्हीं को बड़े जोश से लागू कर रही है। देश में साम्प्रदायिक तनाव व असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा है और इनकी आर्थिक नीति भी जन विरोधी है।

वर्तमान राजनीतिक दशा का लेख 'मोदी की सत्ता का फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं' में सटीक विश्लेषण किया गया है। दिल्ली व विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी पराजय के बाद मध्यप्रदेश की संसदीय सीट व झारखंड की विधानसभा के उप-चुनाव तथा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के निकाय व पंचायती चुनावों में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। इनसे साफ़ पता चलता है कि मोदी सरकार के विरुद्ध असंतोष फ़ैल रहा है और मोदी सरकार की लोकप्रियता में तेज़ी से कमी आ रही है। परन्तु मोदी सरकार के विरुद्ध कोई प्रतिरोध अथवा आन्दोलन नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ़ आरएसएस अपने संगठनों के माध्यम से अपनी हिन्दुत्व की नीति को खुले रूप से बढाने में लगा हुआ है। समय की आवश्यकता है कि मोदी सरकार के विरुद्ध व्याप्त असंतोष को भुनाने में कोई विकल्प सामने आए जिसकी वर्तमान में संभावना नज़र नहीं आ रही है।

नरेन्द्र मोदी अरविंद केजरीवाल की नीतियों व केजरीवाल की कथनी व करनी में अंतर पर स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुर्की/ अरविंद केजरीवाल की नज़र में' के ज़रिए उचित कटाक्ष किया गया है। वर्तमान केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में दिल्ली ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में व्याप्त भ्रष्टाचार और मोदी सरकार का जेटली के बचाव में खड़े होने के सन्दर्भ में लेख ' रावण को मिल गई एक नई सीता' तथा प्रकाशित कार्टून अत्यन्त उपयुक्त है।

महत्वाकांक्षी केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के पर कतरने तथा उसके प्रतिद्वन्दी के रूप में अवसरवादी अवतार भड़ाना को भाजपा में शामिल करने का लेख 'कृष्णपाल की सत्ता में अवतार की सेंघमारी-जन्म दिन तो बहाना है, मकसद सत्ता में आना है' में उचित विवेचन किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च स्तरीय व प्रशंसनीय है।

-प्रो.जुगल किशोर गुप्ता